



कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख्य पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियाँ सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 67

नवम्बर, 2022

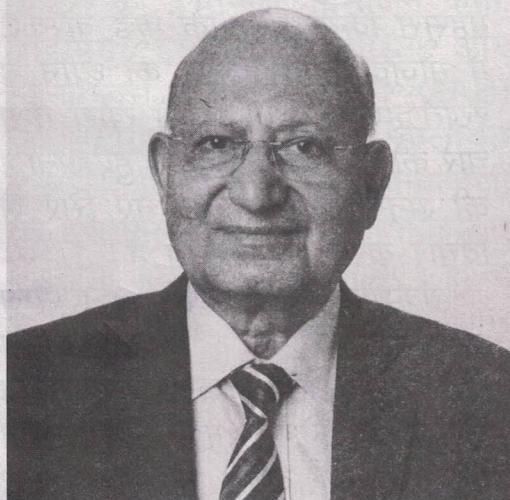
अंक 11

कुल पृष्ठ 8

खाद्यान्ज की उत्पादकता और उनका उत्पादन

बढ़ाने के लिए क्या कदम हैं जल्दी

डॉ. आर.एस. परोदा



फसल और इकोसिस्टम दोनों हिसाब से अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से नीतिगत समर्थन की जरूरत है। किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज और कर्ज देने तथा बेहतर खेती के तौर तरीके बताने की भी जरूरत है ताकि उत्पादकता बढ़ाई जा सके। बायोफोर्टीफाइड वैरायटी/हाइब्रिड का इस्तेमाल बढ़ाया जाना चाहिए। हाइब्रिड फसलों के लिए

बेहतर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) हो और हाइब्रिड चावल अनुसंधान बीज उत्पादन और एक्सटेंशन एजेंसियों के बीच बेहतर लिंकेज हो। जिनोम एडिटिंग (CRISPR / Cas9) जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तत्काल बढ़ाए जाने की आवश्यकता है

भारत की आबादी अभी 139 करोड़ है और 2030 तक इसके 151 करोड़ हो जाने की उम्मीद है। 2030 तक देश में लगभग 35.5 करोड़ टन अनाज की जरूरत पड़ेगी। यानी अभी की तुलना में 5 करोड़ टन अधिक। इसका मतलब है हर साल अनाज उत्पादन लगभग 50 लाख टन बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे में मौलिक सवाल उठता है कि अनाज उत्पादन में क्या भारत आत्मनिर्भर बना रहेगा। उत्पादन बढ़ाने की चुनौती सचमुच गंभीर है क्योंकि प्रति व्यक्ति औसत जमीन और सिंचाई के लिए पानी, दोनों कम होते जा रहे हैं। इसके अलावा बायोटिक और एबायोटिक

दबाव बढ़ता जा रहा है।

दुनिया की आबादी 2050 तक 980 करोड़ हो जाएगी। यह विश्व की मौजूदा आबादी से 34 प्रतिशत अधिक होगी। संयुक्त राष्ट्र की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 79.46 करोड़ अल्प पोषित लोगों में 77.99 करोड़ लोग विकासशील देशों में रहते हैं। अनुमान है कि अगर खानपान का मौजूदा पैटर्न, आमदनी और खपत की परिस्थितियां यही बनी रहीं तो विश्व को 70: अधिक खाद्य पदार्थ की जरूरत पड़ेगी (एफएओ 2009)।

यील्ड यानी उत्पादकता में अंतर कम करने में आ रही दिक्कतों पर चर्चा करने और अनाज उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने की रणनीति पर सुझाव देने के लिए तटस्थ थिक टैक्ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज(तास) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने आईआरआरआई (IRRI), इक्रीसैट और आईसीएआरडीए के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। यह आयोजन 26 अगस्त 2021 को हुआ था। केंद्र और राज्य सरकारों, सीजी सेंटर, वैज्ञानिक संस्थाओं, प्राइवेट बीज उद्योग और किसान संगठनों के 119 प्रतिभागियों ने उस कार्यशाला में हिस्सा लिया।

कार्यशाला के तीन प्रमुख उद्देश्य थे। पहला, यील्ड गैप कम करने के लिए फसल के हिसाब से क्षेत्रों पर चर्चा करना और उन्हें लक्षित करना, दूसरा, अनाज उत्पादन बढ़ाने

के मकसद से फसल और क्षेत्र के हिसाब से उत्पादकता बढ़ाने में आ रही दिक्कतों को पहचानना और उन्हें दूर करने के विकल्प तलाशना तथा तीसरा, अनाज उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ाने के लिए एक स्पष्ट स्ट्रेटजी का सुझाव देना और उसमें आने वाली दिक्कतों को पहचानना।

रणनीतिक पहल

वर्कशॉप में कई बहुमूल्य सुझाव आए और सिफारिशें दी गईं। यह महसूस किया गया कि फूड बास्केट में मौजूदा विविधीकरण को ध्यान में रखते हुए और भविष्य में खाद्य तथा चारे की जरूरतों को देखते हुए अनाज की अनुमानित मांग पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है।

वर्कशॉप में आईसीएआर, एनएएएस और तास की तरफ से एक साझा स्ट्रेटजी पेपर तैयार करने की जरूरत बताई गई, जिसमें भविष्य में अनाज की मांग को देखते हुए खाद्य और चारे की उपलब्धता का विश्लेषण हो। उस स्ट्रेटजी पेपर में विभिन्न अनाज फसलों की उत्पादकता में अंतर को कम करने का एक स्पष्ट रोड मैप हो, फसल वार और राज्यवार यील्ड गैप विश्लेषण हो ताकि सालाना आधार पर प्रमुख अनाजों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जा सके। इनके अलावा हर फसल के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया जाना चाहिए। वर्कशॉप में

डीडीजी क्रॉप साइंस, डीडीजी हॉर्टिकल्चर साइंस, डीडीजी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और कृषि/बागवानी कमिशनर को मिलाकर तत्काल एक समिति बनाने की सिफारिश की गई।

रिसर्च को मजबूत बनाना

जर्मप्लाज्म एनहांसमेंट और प्री-ब्रीडिंग पर जोर देने की जरूरत है। मॉलेक्युलर मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, जिनोमिक सिलेक्शन (GS), ट्रांसजेनिक और जिनोम एडिटिंग (CRISPR/Cas9), स्पीड ब्रीडिंग का इस्तेमाल, प्रिसीजन फेनो, टाइपिंग, इम्पीरिकल ब्रीडिंग और जिनोमिक्स असिस्टेड ब्रीडिंग (GAB) का इंटीग्रेशन और डबल हैप्लॉयड टेक्नोलॉजी जैसी बायो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहतर वैरायटी विकसित करने में बढ़ाया जाना चाहिए। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और आईसीएआर केंद्रों के ब्रीडर को इन टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें एनआईपीबी जैसे आईसीएआर के केंद्रों और इक्रीसैट जैसे सीजीआईएआर के केंद्रों में प्रशिक्षित किया जा सकता है। आईसीएआर की तरफ से 1000 करोड़ रुपए के आवंटन से हाइब्रिड रिसर्च पर राष्ट्रीय मिशन मोड प्रोजेक्ट प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाना चाहिए।

रिसर्च योग्य कई प्रमुख मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर गौर किया जाना चाहिए। इनमें कुछ प्रमुख मुद्दे हैं—चावल के मामले में जीनोम असिस्टेड

ब्रीडिंग का इस्तेमाल एनहांस्ड जेनेटिक फायदे के लिए किया जाना चाहिए। सुपर राइस (प्रति हेक्टेयर 10 टन से अधिक उत्पादन) ज्यादातर इकोलॉजी के लिए विकसित की जानी चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता और सूखे को सहने की बेहतर क्षमता वाले हाइब्रिड गेहूं की किस्मों का विकास किया जाना चाहिए।

मक्के के मामले में जेनेटिक विविधीकरण पर फोकस किया जाना चाहिए। स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, पॉपकॉर्न, स्पेशलिटी कॉर्न, सिंगल क्रॉस और क्यूपीएम हाइब्रिड जैसे स्पेशलिटी मक्के पर अधिक फोकस किया जाना चाहिए। ऐसा करते वक्त उसके पोषण का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। बाजरा के क्षेत्र में दोहरे उद्देश्य वाले हाइब्रिड बीजों का विकास किया जाना चाहिए। यह सबसे सूखे वाले ए1 जोन के प्रति सहनशील, डाउनी मिलडायू के प्रतिरोध, सूखे और गर्भी के प्रति सहनशील तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर हो। इसके अलावा कम अवधि में तैयार और अधिक उत्पादकता वाली दालों की वैरायटी भी विकसित की जानी चाहिए।

विकास के प्रयास

वर्कशॉप में यह महसूस किया गया कि उत्पादकता में अंतर को पाठने के लिए दो तरफा नीति अपनाने की जरूरत है। एक तो उत्पादकता बढ़ाकर वर्टिकल गैप कम करना और दूसरा अधिक क्षेत्रफल में खेती करके

हॉरिजॉन्टल गैप कम करना। फसल विविधीकरण के जरिए गैर पारंपरिक फसलों को बढ़ावा देने की भी जरूरत है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में कम अवधि में तैयार होने वाले काबुली चने की खेती का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना चाहिए। केंद्रीय और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में काला चना, हरा चना, काबुली चना जैसी फसलों की मिश्रित खेती की जा सकती है। उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में कम अवधि में तैयार होने वाली अरहर की किस्म शुरू की जा सकती है। बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में धान के खेतों में मसूर और मटर की खेती की जा सकती है। उत्तर में मूँग को ग्रीष्म फसल के तौर पर प्रमोट किया जा सकता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में दालों तथा दक्षिण के तटीय इलाकों में उड्ढ तथा मूँग की खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है।

राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाजरे की उत्पाद कता बढ़ाने और हाइब्रिड चावल की खेती को बढ़ावा देने की जरूरत है। पूर्वी और मध्य भारत में चावल की जगह सिंगल क्रॉस मक्के की हाइब्रिड किस्म का क्षेत्र बढ़ाया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल और बिहार में मक्के के साथ बोरो चावल की खेती की जानी चाहिए। फली और छोटी मिलेट की पोषण से भरपूर वैरायटी तत्काल विकसित करने की भी आवश्यकता है।

हाइब्रिड फसलों की अधिक उत्पादकता वाली किस्मों की अच्छी क्वालिटी वाले बीज तैयार करने पर फोकस

किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण अनाजों के मामले में सीड रिप्लेसमेंट रेट (SRR) पर भी फोकस किया जाना चाहिए। राज्यों को सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स के लिए 35 फीसदी एसआरआर और क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स के लिए 90 फीसदी (एसआरआर) का लक्ष्य रखना चाहिए।

मौजूदा एक्सटेंशन सिस्टम को नए सिरे से तैयार करने की जरूरत है ताकि इसे निजी क्षेत्र, सिविल सोसायटी और युवाओं को शामिल करते हुए ज्यादा प्रभावी बनाया जा सके। कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) तथा सरकारी निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से हर किसान विकास केंद्र (KVK) एक बेहतर जानकारी और इनोवेशन का केंद्र बन सकता है।

कृषि मंत्रालय तथा आईसीएआर के बीच एक प्रभावी समन्वय की भी जरूरत है। साथ ही राज्यों के कृषि विभागों तथा कृषि विश्वविद्यालयों के बीच भी समन्वय होना चाहिए। मृदा परीक्षण, बीज रेट, बीज ट्रीटमेंट, प्लांट पॉपुलेशन, सिंचाई शेड्यूल, बायोफर्टिलाइजर के इस्तेमाल, बायो कीटनाशकों के इस्तेमाल, अकार्बनिक उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए स्थान विशेष आधारित नीति अपनाने की भी जरूरत है।

नीतियों पर अमल

वर्कशॉप में यह महसूस किया गया कि फसल और इकोसिस्टम दोनों हिसाब से अनाज उत्पादन बढ़ाने के

लिए सरकार की तरफ से नीतिगत समर्थन की जरूरत है। किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज और कर्ज देने तथा बेहतर खेती के तौर तरीके बताने की भी जरूरत है ताकि उत्पादकता बढ़ाई जा सके। बायोफोर्टीफाइड वैरायटी/हाइब्रिड का इस्तेमाल बढ़ाया जाना चाहिए। हाइब्रिड फसलों के लिए बेहतर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) हो और हाइब्रिड चावल अनुसंधान बीज उत्पादन और एक्सटेंशन एजेंसियों के बीच बेहतर लिंकेज हो। जिनोम एडिटिंग (CRISPR/Cas9) जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तत्काल बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

सरकारी निजी साझेदारी और नीतिगत समर्थन के जरिए हाइब्रिड और बायोफोर्टीफाइड फसलों को अधिक अपनाया जाना चाहिए। मक्का किसानों

को उचित उत्पादन इंसेटिव देकर मदद की जानी चाहिए। उन्हें बाजार मूल्य और एमएसपी के बीच अंतर का भुगतान किया जाना चाहिए।

अधिक उपज वाली वैरायटी और हाइब्रिड को तेजी से अपनाने के लिए सरकार को तत्काल नया नीतिगत फैसला लेना चाहिए। इसके लिए प्रतिष्ठित रिसर्च एंड डेवलपमेंट निजी बीज कंपनियों को क्षेत्रवार विशेष लाइसेंस के अधिकार दिए जा सकते हैं, ताकि वे उस क्षेत्र विशेष में अच्छी क्वालिटी के बीज तैयार कर किसानों को बेच सकें। इसके अलावा किसानों को भी किसान संगठनों, कोऑपरेटिव, एफपीओ आदि के माध्यम से संगठित होने और इंडस्ट्री के साथ सीधे जुड़ने की जरूरत है।

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

रबी फसलों का एमएसपी 100 से 500 रुपये तक बढ़ा, गेहूं के एमएसपी में 110 रुपये प्रति किवटल की बढ़ोतरी ऊरल वॉयस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में रबी मार्केटिंग सीजन 2023–24 के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के तहत रबी फसलों के एमएसपी में 100 रुपये से लेकर 500 रुपये प्रति किवटल तक की बढ़ोतरी की गई है।

रबी सीजन की सबसे महत्वपूर्ण फसल गेहूं के एमएसपी में 110 रुपये प्रति किवटल की बढ़ोतरी कर इसे 2125 रुपये प्रति किवटल कर दिया गया है। पिछले सीजन के लिए गेहूं का एमएसपी 2015 रुपये प्रति किवटल था। सरसों के एमएसपी में 400 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और इसके बाद आगामी रबी सीजन के लिए सरसों का

एमएसपी 5450 रुपये प्रति विवर्तन रोगया है। वहाँ सबसे अधिक 500 रुपये प्रति किवर्तन की बढ़ोतरी मसूर के एमएसपी में की गई है। सीसीईए की बैठक के बाद सरकार द्वारा एमएसपी में बढ़ोतरी के संबंध में जानकारी दी गई।

पिछले रबी सीजन में गेहूं के उत्पादन में गिरावट के चलते सरकारी खरीद में भारी गिरावट दर्ज की थी। इसकी वजह गेहूं की कीमतों के एमएसपी से अधिक रहना रहा था। सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद खुले बाजार में देश के विभिन्न हिस्सों में इस समय गेहूं की कीमत 2200 रुपये से 2500 रुपये प्रति विवर्तन के बीच चल रही हैं। ऐसे में गेहूं के एमएसपी में बढ़ोतरी को कम आंका जाएगा।

पंजाब के संगरुर जिले की भवानीखेड़ा तहसील केबिंबर गांव किसान गुरबख्शीश सिंह ने रुरल वॉयस के साथ एक बातचीत में सरकार के एमएसपी के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले गेहूं का उत्पादन कम रहा था उससे किसानों को नुकसान भी हुआ था।

ऐसे में सरकार को गेहूं का एमएसपी कम से कम 2200 रुपये प्रति विवर्तन करना चाहिए था जिससे किसानों को राहत मिलती।

रबी मार्केटिंग सीजन (2023–24) के लिए घोषित एमएसपी में सबसे अधिक 500 रुपये प्रति विवर्तन की बढ़ोतरी मसूर के एमएसपी में की गई है। इस बढ़ोतरी के साथ मसूर का एमएसपी 5500 रुपये प्रति विवर्तन के पिछले एमएसपी से बढ़कर 6000 रुपये प्रति विवर्तन हो गया है। चना के एमएसपी में 105 रुपये प्रति विवर्तन की बढ़ोतरी की गई जो आगामी रबी मार्केटिंग सीजन के लिए 5335 रुपये प्रति विवर्तन हो गया है। वहाँ जौ के एमएसपी में 100 रुपये प्रति विवर्तन की बढ़ोतरी कर इसे 1735 रुपये प्रति विवर्तन कर दिया गया है। सरसों और रेपसीड के एमएसपी में 400 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और इसके बाद आगामी रबी सीजन के लिए सरसों का एमएसपी 5450 रुपये प्रति विवर्तन रोगया है। वहाँ के सैफपलावर एमएसपी में 209 रुपये की बढ़ोतरी गई है जिसके चलते यह 5650 रुपये प्रति विवर्तन हो गया है।

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

खाद्य उत्पादों की निर्यात क्षमता को बढ़ाना भारत के लिए हितकर सिराज हुसैन

कृषि उत्पादों के क्षेत्र में भारत एक मजबूत निर्यातक देश है और इसे अपनी निर्यात क्षमता को निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। यूरोप समेत अन्य देशों की मांग को ध्यान में रखते हुए भारत को अपनी उत्पाद व उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए। उद्योग चैंबर फिक्की के सलाहकार और पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव सिराज हुसैन ने स्मार्ट प्रोटीन समिट 2022 को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं।

स्मार्ट प्रोटीन विषय पर बोलते हुए सिराज हुसैन ने कहा भारत को अपने निर्यात क्षमता को समझना होगा। अब समय आ गया है, जब भारत विदेशों की खाद्य आपूर्ति की मांग को ध्यान में रखते हुए उत्पादन करे। उन्होंने कहा कि सरकार का जोर देश के कुछ हिस्सों को शुद्ध शाकाहारी बना देने पर है। सरकार को मांसाहार को भी बढ़ावा देना चाहिए। पहले जो मांसाहार भोजन की जांच के लिए नगर निगम कि जांच व्यवस्था थी सरकार ने उसे भी खत्म कर दिया। ऐसे में हम खाद्य प्रोटीन की सफलता को कैसे हासिल कर पाएंगे। प्रोटीन प्रोडक्ट्स बेचने वालों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उनके प्रोडक्ट्स को सभी लोग आसानी से खरीद सकें न कि सिर्फ पांच प्रतिशत लोग।

गुड फूड इंस्टीट्यूट इंडिया (जीएफआई) के प्रबंध निर्देशक वरुण

देशपांडे नेस्मार्ट प्रोटीन समिट 2022 को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में इस बात को पाया गया कि एन्टीबायोटिक दवाओं का असर अब लोगों पर बहुत कम होता जा रहा है। यह अच्छी खबर नहीं है। अमेरिका, कतर, इरान में गुड फूड को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट न्यूट्रिशन को बढ़ावा देने के लिए फिक्की और गुड फूड इंडिया (जीएफआई) के सामुहिक प्रयास से नेशनल एक्सीलेंस फार स्मार्ट प्रोटीन (एनआईएसपी) का संस्था का गठन किया जा रहा है।

नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (एनसीएमएल) के चेयरमैन सिराज अजमत चौधरी ने इस मौके पर कहा कि खाद्य से जुड़े विषयों पर हम हमेशा पश्चिमी देशों की समस्याओं को क्रेन्ड में रखकर ही सोचते हैं। हमें अपनी इस आदत को छोड़ना पड़ेगा और अपने देश की समस्याओं को क्रेन्ड में रखकर उसको प्राथमिकता देनी होगी। साल 2021 में भारत ने 40 अरब डॉलर के खाद्य उत्पादों का निर्यात किया था जो कि एक बेहतरीन खबर है। हमें समस्या के समाधान के लिए अपने देश के अनुकूल सोचने की जरूरत है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने देश के निर्यात क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

सार्वजनिक सूचना

भारत कृषक समाज के सदस्यों से अनुरोध है कि वे भारत कृषक समाज के महासचिव के कार्यालय के साथ अपने संपर्क विवरण को अद्यतन करें।

संपर्क विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है:

नाम: _____

सदस्यता संख्या: _____

वर्तमान पता: _____

टेलीफोन नंबर: _____

मोबाइल नंबर: _____

ईमेल: _____

(कृपया पते का सबूत की एक छायाप्रति संलग्न करें)

विधिवत भरा हुआ फॉर्म निम्नलिखित पते पर स्पीड पोस्ट या ईमेल द्वारा इस माह के अन्त तक या उससे पहले जमा कराएँ:

महासचिव

भारत कृषक समाज

ए-1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली, 110013

ईमेल:— Samdarshi.bks@gmail.com

टेलीफोन:— 011-41402278

नोट: आपसे अनुरोध है कि आप अन्य सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए सूचित करें।

भारत कृषक समाज ए-1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली- 110013, फोन: 011-41402278, 9667673186, ई-मेल: ho@bks.org.in, वैबसाईट: www.bks.org.in के लिए श्री उरविन्द्र सिंह
भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल
एरिया, फेस -2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।